भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4497
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डे

4497. श्री के.सी.वेणुगोपाल:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डों का प्रतिशत कितना है;

(ख) सरकार द्वारा प्रमुख हवाई अड्डों को पूर्णतः सौर या पवन ऊर्जा चालित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की आगामी सभी हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अनिवार्य बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी हवाई अड्डों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रोत्साहन दी गई हैं या नीतियां बनाई गई हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): 159 प्रचालनशील हवाईअड्डों में से 81 हवाईअड्डे अर्थात लगभग 51% प्रचालनशील हवाईअड्डों ने 100% हरित ऊर्जा प्रयोग का स्तर प्राप्त कर लिया है।

(ख): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) सहित हवाईअड्डा प्रचालकों ने हवाईअड्डों पर हरित ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के उत्सर्जन तथा स्वयं-उपयोग हेतु विभिन्न स्थलों/ हवाईअड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। साथ ही, कुछ हवाईअड्डें सीधी पहुँच के माध्यम से भी हरित ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अन्य पहलों में भवन का डिज़ाइन तैयार करने के लिए ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुसार भवन डिजाइन को अपनाना, पारंपरिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना, ऊर्जा कुशल हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी), प्रकाश व्यवस्था और बैगेज हैंडलिंग प्रणाली आदि शामिल हैं;

(ग) और (घ): नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने अनुसूचित प्रचालन वाले सभी हवाईअड्डों और आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकासकर्ताओं को कार्बन तटस्थता और नेट जीरो स्थिति प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का सुझाव दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है।

नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाईअड्डों के कार्बन अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग तंत्र को मानकीकृत करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन शमन पर जागरूकता पैदा करने के लिए ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित परिचालन वाले हवाईअड्डा प्रचालकों को अपने-अपने हवाईअड्डों पर कार्बन उत्सर्जन का मानचित्रण करने और चरणबद्ध रूप से कार्बन तटस्थता और नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में कार्य करने का सुझाव दिया गया है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) प्रमुख हवाईअड्डों की टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के दौरान हरित ऊर्जा परियोजनाओं, कार्बन तटस्थता आदि से संबंधित पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखता है।

*****